प्रतिवेदन: हंसराज कॉलेज और आईएलएलएल, दिल्ली विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधन में आयोजित तीन दिवसीय लेक्चर सीरीज का संक्षिप्त रिपोर्ट और NEP की विशेषताएँ

Vinay Gupta, हंसराज कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय

Corresponding mail – vkgj22@gmail.com

नई राष्ट्रीय नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य भारत को विश्व में महाशक्ति और आत्म निर्भर राष्ट्र बनाना है। यह कार्य उच्च गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के माध्यम से हो सकता है। इसलिए इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा की सार्वभौमिकरण और समग्रता पर अधिक ध्यान दिया गया है। नई शिक्षा नीति को संक्षिप्त रूप से NEP कहा जाता है। यह देश में शिक्षा के विकास का मार्गदर्शन करने वाली मील का पत्थर है। जिसके माध्यम से शिशु के बालमन से लेकर स्किल/ नॉन स्किल, शोधार्थी सभी के मानसिक और शारीरिक अप्रोच का संतुलित विकास होगा।

शिक्षा किसी भी राष्ट्र के विकास का सबसे महत्वपूर्ण अंग होती है। आजाद भारत में अभी तक तीन शिक्षा नीतियाँ आ चुकी हैं जिनमें से एक है "नई शिक्षा नीति-2020 इस तीसरी कड़ी में शिक्षा व्यवस्था में प्राथमिक से लेकर उच्चतर शिक्षा में व्यापक बदलाव किये गये है, समयोचित हैं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है यह परिवर्तन भारतीय शिक्षा पद्धति में इस कदर हुआ है कि पूर्णत: कायापलट सी प्रतीत होता है, क्योंकि कोरोना आने से पहले जहाँ ज्यादातर पद्धति ऑफलाइन थीं, वहीं कोरोना के प्रकोप के दौरान लॉकडाउन लगने से ज्यादा सारी चीजें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आ गई, जिससे शिक्षा अछूती नहीं रही ।

जब से यह शिक्षा नीति चर्चा में आई तब से लेकर अब तक सैकड़ों सेमिनार अनेक स्कूलों, कॉलेजों व विश्वविद्यालयों में हो चुके हैं। इसी प्रक्रिया में दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज महाविद्यालय में तीन दिवसीय ऑनलाइन वेबिनार (जनवरी 2022) आयोजित किया गया। जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो० योगेश सिंह, प्रो बलराम पाणी , प्रो.विकास गुप्ता, हंसरज महाविद्याल की प्राचार्या डॉ० रमा व अन्य अनेक वक्ताजन शामिल हुए, साथी ही देश के कोने-2 से श्रोताओं ने भागीदारी प्रस्तुत की। सभी वक्ता ने नई शिक्षा नीति-2020' के संबंध में अनेक सकारात्मक पहलुओं को सामने उजागर किया, साथ ही यह भी बताया कि आगामी समय में भारत किस प्रकार से

विकास के पथ पर सवार होते हुए नवाचार के क्षेत्र का एक हब बनेगा, इसमें इस शिक्षा नीति का महत्वपूर्ण योगदान होगा।

प्रो.योगेश सिंह (कुलपति, दिल्ली विश्वविद्यालय) के प्रमुख विचार

पिछले 2 सालों में हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर बहुत चर्चा की , मैं मानता हूँ कि इस पर हजारों सेमिनार वेबीनार आदि हुए| इस नीति के केंद्र में छात्र है और भारत है| यह नीति सैद्धांतिक शिक्षा पर बल देती है| यह नीति सहयोग और समन्वय पर बल देती है| नई शिक्षा नीति को लागू करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए| हालांकि यह एक चुनौती है जिसे हमें स्वीकार करना चाहिए| उन्होंने अरस्तु की शिक्षा की परिभाषा का उल्लेख किया- शिक्षा हमें साथ रहना सिखाती है| इसके बाद भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुसार शिक्षा की परिभाषा को भी उल्लेखित किया कि शिक्षा ही एक अच्छी समझ विकसित कर सकती है.

- इसके बाद उन्होंने शिक्षा के उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए चाणक्य के विचारों को प्रस्तुत किया- शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है, एक शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है, शिक्षा यौवन और सौंदर्य को परास्त करने की क्षमता रखती है| शिक्षा का उद्देश्य एक संवेदनशील नागरिक का निर्माण करना है| इसके बाद उन्होंने नई शिक्षा नीति को लागू करने में आने वाली चुनौतियां के बारे में बताया और साथ में उससे निपटने का भी सुझाव दिया| उन्होंने छात्रों के द्वारा विषय चुनने की स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण माना| अगर कोई छात्र फिजिक्स के साथ साइकोलॉजी पढ़ना चाहता है तो उसे उसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए |यदि वह हिंदी पढ़ना चाहता है या अंग्रेजी पढ़ना चाहता है तो उसे यह स्वतंत्रता होनी चाहिए और नई शिक्षा नीति छात्रों को यह स्वतंत्रता प्रदान करती है| नई शिक्षा में स्किल्स और इंटरशिप को बढ़ावा दिया गया है| इसके बाद उन्होंने शिक्षकों को यह आश्वासन दिया कि नई शिक्षा नीति के तहत और शिक्षकों की जरूरत है ना कि हम शिक्षकों की कमी चाहते हैं| उन्होंने बताया कि नई शिक्षा नीति छात्रों के सिर्फ शिक्षा पर ही नहीं बल्कि अन्य गतिविधियों(sports etc.) पर भी बल देती है| नई शिक्षा नीति का विरोध करने वाले शिक्षकों से उन्होंने विरोध न करने की अपील की और नई शिक्षा नीति के फायदों को समझाया|

- हमें उस शिक्षा पर जोर देना चाहिए, जो शिक्षा सहयोग सिखाएं, ना कि स्वार्थी होने पर जोर दे, और यह नई शिक्षा नीति सहयोग की प्रेरणा देती है| हर्बट हुवर की कहानी के माध्यम से उन्होंने शिक्षा में सहयोग की भावना की महत्ता बताई|उन्होंने कहा कि शिक्षा सिर्फ अंकों के लिए नहीं बल्कि सहयोग की भावना को प्रेरित करने के लिए होनी चाहिए| उन्होंने नई शिक्षा नीति की लागू करने संकल्प के साथ अपने वक्तव्य को

समाप्त किया|

डॉ. विकास गुप्ता (रजिस्ट्रार, दिल्ली विश्वविद्यालय)

सर ने कहा कि शिक्षा वो मौलिक साधन है, जिससे मानव अपनी क्षमता को व्यवहारिक कर पाता है और समाज में न्याय और समता को सहज रूप से स्थापित कर पाता है और शिक्षा राष्ट्रीय विकास में भी अतिआवश्यक चीज है| व्यक्ति के व्यवहार से लेकर देश की अर्थव्यवस्था तक में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है| शिक्षा हमें अधिक दयालु और समाज की देखभाल करने हेतु प्रोत्साहित करती है| शिक्षा राष्ट्रीय अखंडता और सांस्कृतिक संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है| नई शिक्षा नीति, भारत राज संघ की प्रतिबद्धता है और इसके माध्यम से भारत विश्व पटल पर एक मुख्य निर्देशक तौर पर शीघ्र उभरेगा| आज के इस दौर में हमें यह शिक्षा नीति बताती है कि हमें सिर्फ किसी चीज का ऊपरी ज्ञान नहीं लेना चाहिए अपितु सतह पर जाकर उसके बारे में जानकारी लेते हुए उसे सीखना और समझना चाहिए | साथ ही साथ नाजुक परिस्थितियों में हम संवेदनशील होने के पश्चात किस भांति समस्या का समाधान कर सके, इस बात हेतु भी हमें नई शिक्षा नीति परिपक्व करती है| साथ ही साथ हमारी रचनात्मकता, multi disciplinary चीजों पर भी इसका बहुत ज्यादा प्रभाव होने वाला है|इस बदलते दौर को सहज स्वीकार कर नवाचार पर विचार करने हेतु भी प्रेरित कर रही है| इस शिक्षा नीति में मुख्य तौर पर कला, खेल, भाषा, साहित्य, मूल्य इत्यादि पर जोर दिया गया है, जो कि इसे भूतपूर्व की नीतियों से पृथक करता है| आज हम इस नीति के तहत वैल्यू एजूकेशन और स्किल एजूकेशन को यूजीसी के पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर रहे हैं ताकि छात्र एक वर्ष पढ़ाई के बाद भी अगर पढ़ाई छोड़ दो तो उसके भीतर इतना सामर्थ्य हो (vocational education knowledge)कि वो सही से अपनी आजीविका चला सके और साथ ही साथ वो जब चाहे पुनः अपनी पढ़ाई शुरू कर सकेंगे| नई शिक्षा नीति के तहत अब छात्र अपनी इच्छा अनुसार किसी भी विषय को G. E विषय के तौर पर चयन कर सकेंगे |उसमें उसे किसी भी बाधा का सामना नही करना पड़ेगा| साथ ही साथ सर ने यह भी कहा कि समसमायिक निर्धारित फ्रेमवर्क पर चर्चा होती रहेगी और समयानुसार शिक्षा को बेहतर ढंग से पहुचाने हेतु इसमें आवश्यक परिवर्तन किया जाता रहेगा|

प्रो. रमा (प्रिंसिपल, हंसराज कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय)

नई शिक्षा नीति-2020 का प्रयोजन शैक्षिक क्षेत्र में भारत को वैश्विक महाशक्ति बनाना है और भारत के लिए नई शैक्षिक नीतियां के माध्यम से संपूर्ण भारत में शिक्षा का उचित स्तर प्रदान करना है, जिससे शैक्षिक क्षेत्र की गुणवत्ता उच्च हो सके।

भारत में बच्चों को तकनीकी तथा रचनात्मक्ता के साथ-साथ शिक्षा की गुणवत्ता का महत्व से अवगत कराना, नई शिक्षा नीति का प्रयोजन है जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सके। शिक्षा में गुणवक्ता लाने के लिए यह केंद्र सरकार के तहत नई शिक्षा नीति को शुरू किया गया है। नई शिक्षा नीति से पहले इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखते है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि देश ने पहला शिक्षा नीति घोषित किया, इससे पहले भी शिक्षा नीति आई है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि पहले और अब के शिक्षा नीति में क्या अंतर है, और क्यों अंतर है। एक बात और जानना चाहिए कि हर समय में तत्कालीन सरकार अपनी सोच के अनुसार शिक्षा नीति घोषित करती है। शिक्षा हर समाज और देश के महत्वपूर्ण अवयव है, जितनी अच्छी और गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा होगी, उसीतरह समाज का निर्माण होगा। शिक्षा अपने आप में अध्ययन और अध्यापन की दुनियां नहीं है बल्कि समाज के निर्माण की पाठशाला है। शिक्षा का बीज समाज और देश को आगे बढ़ाता है। शिक्षा के माध्यम से एक पूरा समाज और देश की विचारधारा को बदला जा सकता है। भारत जब अंग्रेजों उपनिवेश था, अंग्रेजों ने सबसे अधिक भारतीय शिक्षा और संस्कृति की उपेक्षा की। अंग्रेज चाहते थे कि भारतीय शिक्षा खंडित हो जायेगी तो फिर भारतीय अँगरेजी नीति के पक्षधर हो जाएंगे। यह सच है कि किसी देश को गुलाम बनाना है तो सबसे पहले उस देश की शिक्षा और संस्कृति को खत्म कर दो, तो वह देश स्वयं उपनिवेश का गुलाम हो जाता है, यही नीति अंग्रेजी शासकों ने उठाई थी। उन्होंने भारत में सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था के लिए कलकत्ता में 1800 ई. में फोर्ट विलियम कॉलेज खोला, जो अंग्रेज नौकरशाहों, अधिकारियों, कर्मचारियों को भारतीय सामाजिक व्यवस्था से अवगत कराना चाहा और साथ में भारतीयों पर अपने शासन को दीर्घ और स्थायी बनाने के लिए व्यवस्था थी। 1835 ई. में लार्ड मैकाले ने भाषा के लिए अंग्रेजी भाषा को प्रश्रय दिया,यहीं से भारत इंडिया बनने लगा, और आज हम इसके दुष्परिणाम देख रहे है। यह सिर्फ अंग्रेजी भाषा का बदलाव या लागू करना नहीं था बल्कि मैकाले की अंग्रेजी नीति ने भारतियों के अंदर विभाजन पैदा की। फिर 1868 ई. में हंटर कमीशन आया जो मातृभाषा का पक्षधर था, लेकिन तब तक इतने भाषाई विवाद बन गए थे, कोई अंतिम निर्णय नहीं हो सका। भारत की आजादी के बाद भी शिक्षा व्यवस्था और भाषा का सही रूप देने के लिए यू जी सी और साहित्य अकादमी की स्थापना हुई, लेकिन यह पूर्णतया सफल नहीं हो सके। इसके लिए भारत में एक अलग से नीति बनाने की आवश्यकता हुई , स्वतंत्र भारत में पहली बार 1968 में शिक्षा नीति बनी। उसके बाद 1986 में शिक्षा नीति बनी, फिर इसके कमियों को दूरकर , संधोधित रूप में 1992 में घोषित किया गया। 1986

से 2020 तक 34 वर्षो में कोई शिक्षा नीति घोषित नहीं हुई। नई शिक्षा नीति केओ दिल्ली विश्वविद्यालय लागू करने वाला है, यह सराहनीय कदम है, बच्चों के लिए उपयोगी है। नई शिक्षा नीति का दिल्ली विश्वविद्यालय में स्वागत है।

प्रोफ़ेसर के॰रत्नावली (Dean Academic Activities and Projects ,University of Delhi)

हमारी नई शिक्षा नीति बहुत अच्छी है लेकिन साथ में बहुत विस्तृत है अतः इसे लागू करना चुनौतीपूर्ण है लेकिन बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है। | उन्होने अपना प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख बिंदुओं पर बात की| जिसके तहत बताया कि यह शिक्षा नीति छात्र केंद्रित, लचीली, समानता को बढ़ाने वाली, शोध और रचनात्मकता पर केंद्रित और बहुभाषी सिद्धांत को प्रमोट करने वाली है| उन्होंने बताया कि सभी स्नातक के विषयों के लिए एक फ्रेमवर्क है ,ना कि अलग-अलग| उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे कोई स्टूडेंट अगर फिजिक्स से स्नातक कर रहा है तो वह जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में जर्मन भाषा को भी ले सकता है| उन्होंने बताया कि यह फ्रेमवर्क flexibility और multidisciplinrity पर जोर देता है| यह Holistic Education को बढ़ावा देता है | AECC ,SEC,GE के माध्यम से इस पर जोर दिया जाएगा| उन्होंने बताया कि इसके तहत रिसर्च पर जोर देने के लिए छठवीं सेमेस्टर में 'Research Methodology' विषय के रूप में प्रदान किया जाएगा| इसके तहत बहुभाषावाद को बढ़ाने के लिए प्रत्येक स्नातक के छात्र को दो सेमेस्टर में आठवीं अनुसूची में से कोई एक भाषा का अध्ययन कराया जाएगा| इस फ्रेमवर्क में मोबिलिटी आफ स्टूडेंट्स पर भी जोड़ दिया गया है| इसके बाद उन्होंने Discipline Specific Core(DSC) ,Discipline specific Elective (DSE),General Elective (GE) को स्पष्ट किया| उन्होंने स्नातक के विभिन्न कोर्सों के क्रेडिट एवं पेपर्स की विस्तृत जानकारी दी|

उन्होंने 'Major' and 'Minor' discipline for single and multi core discipline UG programme को अच्छे से समझाया| उन्होंने UGCF 2022 के विभिन्न प्रोग्राम की जानकारी दी और पुराने प्रोग्राम से इसकी भिन्नता को स्पष्ट किया|

प्रो. श्री प्रकाश सिंह (निदेशक, दक्षिण परिसर, डी. यू.)

संदर्भ यह है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में अंडर ग्रैजुएट कोर्स इसके लिए एक कर्कुलम जारी किया और यह कर्कलम बहुत सोचा, समझा, विचारा हुआ कर्कुलम है और जब मैं यह बात कह रहा हूँ तो इसके पीछे मेहनत और जो परिश्रम NEP सेल ने जो किया है वो तो किया ही किया है और वाइस चांसलर के द्वारा हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट के बीच, कॉलेज प्रिंसिपल्स के बीच, जो शिक्षक इकाई है उसके द्वारा हुआ है हम सबके बीच में चर्चा के

केंद्र में हैं वह एक मॉडल है जिसमें क्रेडिट सिस्टम 176 तक दिए गये। भारत की शिक्षा व्यवस्था वर्तमान समय में औपनिवेशिक चरित्र को बढ़ाने वाली शिक्षा व्यवस्था है और इस चरित्र को व्यवस्थित रूप में पहली बार अगर किसी ने हटाने का प्रयास किया है हमारे मानस को डिकॉलोनाइज करने का प्रयास किया है तो यह प्रयास राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा किया गया । राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कैसे क्रियान्वित किया जाए तो सघन प्रयास दिल्ली विश्वविद्यालय ने किया और दिल्ली विश्वविद्यालय की इस प्रयास को आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए. इसको समग्रता में देखना चाइए देखना चाहिए। विश्वविद्यालय लगभग 6 लाख अकादमी की जरूरत को पूरा करता है। गुणवत्ता के साथ पूरे देश में शिक्षा देता है और अपनी साख को भी बनाए हुए है महामारी के कालखंड में भी उसने अपनी साख को बनाए रखा और जो मानक तत्व को भी उसने स्वीकार किया,। मुझे पूरा विश्वास है इसमे लचिलापन है, कालेज के लिए अच्छा है। इस नीति को अगले अकादमिक सत्र से लागू करना चाहते हैं, यह सरहनीय कदम है।

प्रो.पंकज अरोड़ा (Director ILLL, University of Delhi)

यह फ्रेमवर्क देश में 4 वर्ष की स्नातक कोर्सों के लिए मार्गदर्शन का काम करेगा| राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रमुख बिंदु Multidisciplinary, Interdisciplinary, skill enhancement, promotion of constitutional values हैं| उन्होंने बताया कि दिल्ली विश्वविद्यालय किस तरह विभिन्न समयों में अपनी प्रोग्रामों में परिवर्तन कर चुका है| औरUGCF2022 को भी सफलतापूर्वक लागू करने में सक्षम है| यह curriculum 100% छात्र केंद्रित है| यह NEP curriculum program एक चक्रीय प्रक्रम के अनुसार सक्रिय रहेगा|

- इस फ्रेमवर्क पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा के सभी उद्देश्य(physical development,Mental development,emotional development,intellectual development,cognitive development) पूरे होते हैं| यह नीति पुरानी भारतीय संस्कृति और 21वीं सदी के युवा को एक साथ लेकर चलने में सक्षम है| यह पाठ्यक्रम भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देता है| नई शिक्षा नीति आर्थिक विकास के साथ-साथ सामाजिक एवं शैक्षिक विकास को भी बढ़ावा देती है| छात्रों को स्नातक स्तर पर स्वतंत्रता देनी चाहिए| चार-पांच घंटे से ज्यादा कक्षा में अध्ययन नहीं किया जाना चाहिए| छात्रों को अन्य गतिविधियों में सपोर्ट करना चाहिए| इस पाठ्यक्रम में इन सब बातों का ध्यान रखा गया है| यह नीति एंपलॉयर्स के साथ जोड़ने का रास्ता देती है| उन्होंने नीति के संपूर्ण परिणाम को देखने का सुझाव दिया ना कि उसे टुकड़े- टुकड़े में विभाजित कर देखने में| क्योंकि यह नीति प्रगतिशील एवं लचीली है| यह नीति छात्रों को तैयार करती है

21वीं सदी के लिये और एक श्रेष्ठ भारत और विकसित भारत बनाती है|

प्रोफेसर बलराम पाणी (Dean of Colleges, University of Delhi

दो वर्षों से इस पर चर्चा करते आ रहे हैं| पर आज हम इसके कार्यान्वयन हेतु आवश्यक गतिविधियों पर चर्चा करेंगे| यह बहुत खुशी की बात है कि सरकार इतनी उपयोगी नीति को लागू करने के लिए पूरी प्रयासरत है| इस नीति को बने दो वर्ष होने को है और अभी सरकार इसे हर शिक्षा के स्तर पर लागू करने हेतु कई पहल कर रही है ताकि हर शिक्षा क्षेत्र में इसे सही ढंग से कार्यान्वित किया जा सके| सर ने बताया की नई शिक्षा नीति के तहत बने यूजीसी फ्रेमवर्क छात्रों को continuous learning का सुअवसर देता है जिसमें छात्र अपने कोर्स की अवधि को अपने सुविधानुसार पूर्ण कर सकते हैं| साथ ही साथ उच्च शिक्षण संस्थानों में क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा देने की बात करता है, जिसके माध्यम से क्षेत्रीय भाषा में 10+2 तक पढ़े छात्र भी बड़ी सहजता से उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे| इस नीति के माध्यम से भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर होगा क्योंकि इस नीति का एक उद्देश्य उच्च शिक्षा का वैश्वीकरण है|

नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करना भारतीय शिक्षा व्यवस्था के लिए एक मील का पत्थर है। हमे 2 वर्ष का समय इस पर विचार करने तथा इसे किस प्रकार से लागू किया जाए तय करने को मिला, जिसका परिणाम है की सरकार अब अच्छी गति से इसका पालन कर सकती है। इन नीतियों मे प्राथमिक स्तर, इंजीनियरिंग शिक्षा, बैंक मे भविष्य, अध्यापको के प्रशिक्षण आदि पहल की गयी है। उच्च स्तरीय शिक्षा के विषय मे बात करे तो Academic bank of credit (ABC), Multiple entry and Exit system(EES) छात्रो को उनकी इच्छा के अनुसार विषय चुनने मे सहायक होंगी। साथ ही नई शिक्षा नीति हमें अपनी उच्च स्तरीय शिक्षा को वैश्विक स्तर पर पहचान बनाने तथा भारतीय छात्रो को विदेश मे शिक्षा ग्रहण करने मे भी सहायक है। जैसा की हमे पता है की भारत को अपनी शिक्षा व्यवस्था के कारण ही विश्व गुरु कहा जाता था, ये शिक्षा नीति भी उस लक्ष्य को पुनः प्राप्त करने की एक पहल है। उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे अन्य बड़े संस्थानों को साथ आकर एक निश्चित नियम, प्रणाली, और मानक बनाये चाहिए जिससे सभी लोगो को समान अवसर प्राप्त हो। इसी के द्वारा नई शिक्षा नीति को उसके उद्देश्य मे सफल बनाया जा सकता है।

प्रो. जसबिंदर सिंह (प्रिंसिपल,श्री गुरु तेग बहादुर कॉलेज, डी.यू.)

सर ने वर्तमान की पारिस्थितियों से सभी को अवगत कराया कि आज किस प्रकार से हमने विषयों को विभाजित कर दिया है, और एक छात्र

को अध्ययन करने हेतु एक सीमा में बांध दिया है जो कि उसे व्यापक नहीं होने दे रहा|आज हम सीखने और कौशल पर ध्यान नही दे रहे| क्षेत्रीय भाषाओ में शिक्षा देने वाली बहुत कम उच्च शिक्षण संस्थान है , जो कि समाजिक आर्थिक विकास हेतु पर्याप्त नहीं|

लेकिन इस नई शिक्षा नीति के तहत निर्मित इस फ्रेमवर्क द्वारा हम परिवर्तन में अग्रसर है| उच्च शिक्षण संस्थान अब क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा देने की पहल करेंगे और साथ ही ज्यादा से ज्यादा multidisciplinary विषयों को यूजीसी के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा| और साथ ही साथ पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र में भी सुधार किया जाएगा| Gross Enrollment Ratio को नीति के फ्रेमवर्क के तहत 2035 तक 50% करना है जिसके हेतु हमें अब तक चली आ रही नियमावली से ऊपर उठकर सहज वातावरण निर्मित करना होगा, समग्र और multidisciplinary एजूकेशन के तहत, हमें विषय चयन को सहज बनाना होगा| सर ने शिक्षण और अनुसंधान को एक साथ लेकर चलने की भी बात की|

अगर हम बात करे उच्च स्तरीय शिक्षा मे तो वहाँ science, Art और अन्य प्रोग्राम जैसे engineering प्रोग्राम आदि मे कोई संबंध नही है, नई शिक्षा नीति इस जुड़ाव को बनाने के तरफ एक पहल है। अगर देखे तो ज्यादातर महाविद्यालय केवल आर्थिक मजबूती के लिए ही केंद्रित रहते है जिसे कारण वो रिसर्च आदि पर ध्यान नही देते ये उच्च स्तरीय शिक्षण व्यवस्था मे एक बड़ी समस्या है। NEP रिसर्च के आधार पर यूनिवर्सिटी तथा कॉलेज को ये अधिकार देती है की वो अपना कोर्स आदि को स्टूडेंट के भविष्य मे सहायक विषय पर केंद्रित करे। जिससे यूनिवर्सिटी तथा कॉलेज की रैंकिंग मे बढ़ावा तथा स्टूडेंट को भविष्य निर्माण मे भी सहायक होग। दिल्ली यूनिवर्सिटी को अपना फ्रेम वर्क कॉलेज के भौगोलिक वातावरण को ध्यान मे रख कर बनाना चाहिए जैसे - अगर किसी कॉलेज मे होम साइंस के लिए पर्याप्त सुविधा न हो तो वहाँ ले छात्रो को ये अवसर मिले की वो अन्य कॉलेज मे जाकर इसका प्रशिक्षण प्राप्त करे। कॉलेजों को कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ मिल कर कार्य करना चाहिए जिससे छात्रों को सरलता से intership आदि का लाभ मिल सके।

प्रो निरंजन कुमार (हिन्दी विभाग , दिल्ली विश्वविद्यालय)

सर ने शिक्षा के तीन मुख्य उद्देश्य की चर्चा की- छात्र हित, राष्ट्र हित और ज्ञान हित| वो फिर यूजीसी फ्रेमवर्क की बातों को रखते हुए छात्र केंद्रिकता की बात करते हैं अर्थात प्रत्येक छात्र चाहे वो किसी गाँव के स्कूल से दिल्ली विश्वविद्यालय आया हो या दिल्ली बम्बई के किसी बड़े स्कूल से उसे इस नई

शिक्षा नीति के तहत नए यूजीसी फ्रेमवर्क के अंतर्गत सभी को एक समान अवसर मिलेगा| उन्होंने बताया कि इस फ्रेमवर्क से छात्र एक साथ major and minor डिग्री ले सकेंगे, जो कि पूरे आधुनिक भारत में अभूतपूर्व है| उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत बने इस फ्रेमवर्क के माध्यम से मैकाले शिक्षा प्रणाली से मुक्ति मिलेगी और छात्र स्वयं के बल पर निज रोजगार उत्पन्न करने में सक्षम होंगे और महात्मा गांधी का रोजगार आधारित शिक्षा का ध्येय भी प्राप्त होगा| सर ने कहा कि आजादी के इस अमृत महोत्सव में स्नातक शिक्षा सही मायनों में प्रवासीय शिक्षा नीति से आजाद हो रही है और यह छात्र और राष्ट्र हित में है|

पाठ्यक्रमों मे एनसीसी की शुरुआत

आप सभी जानते हैं नई शिक्षा नीति के अंतर्गत एनसीसी को प्रोत्साहन देने का प्रावधान है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यूजीसी एवं एनआईसीटी द्वारा एनसीसी को विश्वविद्यालयों में एक वैकल्पिक विषय के रूप में चुनाव किए जाने का निर्णय लिया गया है। एनसीसी के माध्यम से देश के विद्यार्थी अनुशासित एवं देश भक्त बनेगें, एनसीसी के लिए एक सामान्य विकल्प क्रेडिट पाठ्यक्रम होता है। जिसकी जानकारी एनसीसी निदेशालय के कमांडिंग अफसर द्वारा सभी विश्वविद्यालयों तथा टेक्निकल संस्थानों के कुलपतियों को प्रदान की गई है। इस पाठ्यक्रम के बारे में भी कमांडिंग अफसर द्वारा विस्तृत जानकारी प्रोजेक्शन एवं ब्रीफिंग के द्वारा प्रदान की गई है।

उनके द्वारा यह भी जानकारी दी गई है कि वर्ष 2021–22 के पाठ्यक्रम में कई विश्वविद्यालयों में एनसीसी को एक वैकल्पिक विषय बनाया जाएगा। वे सभी छात्र जो एनसीसी कैडेट के रूप में दाखिला प्राप्त करेंगे उन्हें क्रेडिट बी और सी प्रमाण पत्र के अलावा शैक्षणिक क्रेडिट भी प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा उनको विभिन्न केंद्र एवं राज्य सरकार की योजना के अंतर्गत दिए जाने वाली रोजगार सुविधाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा।

नई शिक्षा नीति की पृष्ठभूमि

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 1986 में बनाया गया था एवं 1992 में संशोधित किया गया था।
- इस नीति को बने हुए 3 दशक से अधिक समय बीत चुका है।
- इस अवधि के दौरान समाज की अर्थव्यवस्था एवं दुनिया में कई परिवर्तन हुए हैं।
- इसी बात को ध्यान में रखते हुए शिक्षा क्षेत्र द्वारा 21वीं सदी की मांगों को और जरूरतों के प्रति छात्रों को तैयार करने के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लांच की गई।

- इस शिक्षा नीति को एक समावेशी, भागीदारी और समग्र दृष्टिकोण को अपनाते हुए परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से तैयार किया गया है।
- जिसमें विशेषज्ञों की राय, क्षेत्र के अनुभव, अनुभव जन अनुसंधान, हितधारक प्रतिक्रिया आदि को ध्यान रखा गया है।
- नई शिक्षा नीति को तैयार करने के पश्चात इसको पोर्टल पर अपलोड किया गया था।

- जिसमें साधारण जनों और हितधारकों के विचार, सुझाव, टिप्पणियां प्राप्त की गई।
- पोर्टल पर अपलोड करने के बाद राज्य, संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों एवं भारत सरकार के मंत्रालय को द्वारा अपने विचार और टिप्पणी देने के लिए आमंत्रित किया गया।
- इस नीति को 22 भाषाओं में अपलोड किया गया था।
- इसके अलावा इस संबंध में शिक्षा सचिवों के साथ बैठक भी की गई एवं कई राज्यों में शिक्षा संवाद भी किए गए।

नई शिक्षा नीति के सिद्धांत

- प्रत्येक बच्चे की क्षमता की पहचान एवं क्षमता को विकसित करना
- एक सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में निवेश करना
- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को विकसित करना
- बच्चों को भारतीय संस्कृति से जोड़ना
- बच्चों को सुशासन सिखाना एवं सशक्तिकरण करना
- शिक्षा नीति को पारदर्शी बनाना
- तकनीकी यथासंभव उपयोग पर जोर
- विभिन्न प्रकार की भाषाएं सिखाना
- बच्चों की सोच को रचनात्मक एवं तार्किक बनाना

नई शिक्षा नीति की पहल

नई शिक्षा नीति स्वतंत्र भारत के तीसरी शिक्षा नीति है जिसमें बुनियादी तौर पर बदलाव किए गए हैं।

- नई शिक्षा नीति के तहत शैक्षिक क्षेत्र को तकनीकी से भी जोड़ा जाएगा जिसमें सभी स्कूलों में ज्यादा से ज्यादा डिजिटल एक्यूमेंट दिए जाएंगे।
- नई शिक्षा नीति में सभी प्रकार की शैक्षिक विषय वस्तु को प्रमुखता उस क्षेत्र की क्षेत्रीय भाषा में भी ट्रांसलेट किया जाएगा जिससे शैक्षिक क्षेत्र में क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा मिल सके ।
- छठवीं कक्षा से बच्चों को व्यवसायिक परीक्षण इंटर्नशिप दे दी जाएगी।
- नई शिक्षा नीति के भीतर अब पढ़ाई में कई प्रकार के अन्य विकल्प बच्चों को दिए

जाएंगे। अब दसवीं कक्षा में अन्य विकल्पों को भी रखा जाएगा जिसमें छात्र कोई स्ट्रीम ना चुनकर अपनी इच्छा अनुसार विषयों को चुन सकेगा।

- नई शिक्षा नीति के अंतर्गत छात्रों को छठवीं कक्षा से ही कोडिंग सिखाई जाएगी।
- शैक्षिक क्षेत्र में वर्चुअल लैब को भी बनाया जाएगा जिससे शैक्षिक क्षेत्रों की गुणवत्ता को उच्च किया जा सके।
- नई शिक्षा नीति के तहत वर्षों से चली आ रही 10 + 2 के शैक्षिक पैटर्न को बदलकर 5+3+3+4 के नए शैक्षिक पैटर्न को चुना गया है जिसमें 3 साल की फ्री New Education Policy PDF (NEP) नेशनल एजुकेशन पालिसी 2021 – नई शिक्षा नीति | National education policyस्कूली शिक्षा बच्चों को दी जाएगी।
- नई शिक्षा नीति के भीतर शिक्षा का सार्वभौमीकरण किया जाएगा जिसमें कुछ शैक्षिक क्षेत्रों को शामिल नहीं किया गया है जैसे मेडिकल तथा लाॅ।

नई शिक्षा नीति के चरण

नेशनल एजुकेशन पालिसी को चार चरणों में विभाजित किया गया है जो कि 5+3+3+4 पैटर्न है। इस नए पैटर्न में 12 साल की स्कूली शिक्षा तथा 3 साल की प्री स्कूली शिक्षा शामिल है।न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को सरकारी तथा प्राइवेट दोनों संस्थानों को फॉलो करना होगा। न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2021 के चार चरण कुछ इस प्रकार है।

फाउंडेशन स्टेज

फाउंडेशन स्टेज 3 से 8 साल तक के बच्चों के लिए हैं। जिसमें 3 साल की प्री स्कूल शिक्षा तथा 2 साल की स्कूली शिक्षा (कक्षा एक तथा दो) शामिल है। फाउंडेशन स्टेज के अंतर्गत भाषा कौशल और शिक्षण के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

प्रिप्रेटरी स्टेज

प्रिप्रट्री स्टेज के अंतर्गत 8 साल से लेकर 11 साल तक के बच्चे आएंगे। जिसमें कक्षा 3 से 5 तक के बच्चे शामिल है। इस स्टेज में बच्चों की भाषा और संख्यात्मक कौशल में विकास करना शिक्षकों का उद्देश्य रहेगा। इस स्टेज में बच्चों को क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाएगा।

मिडिल स्टेज

मिडिल स्टेज के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 तक के बच्चे आएंगे। कक्षा 6 से बच्चों को कोडिंग सिखाई जाएगी और उन्हें व्यवसायिक परीक्षण के साथ-साथ इंटर्नशिप भी प्रदान की जाएगी।

सेकेंडरी स्टेज

सेकेंडरी स्टेज में कक्षा 9 से 12 तक के बच्चे आएंगे। जैसे कि पहले बच्चे साइंस, कॉमर्स तथा आर्ट्स स्ट्रीम लेते थे। परंतु अब यह खत्म कर दिया गया है। अब बच्चे अपनी पसंद का सब्जेक्ट ले सकते हैं। जैसे कि बच्चे साइंस के साथ कॉमर्स का या फिर कॉमर्स के साथ आर्ट्स के भी ले सकते हैं।

वोकेशनल स्टडीज पर फोकस

हमारे देश में वोकेशनल स्टडी सीखने वाले छात्र 5% से भी कम है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा नीति के अंतर्गत कक्षा छठी से कक्षा आठवीं तक के छात्रों को वोकेशनल स्टडीज सीखने पर ध्यान दिया जाएगा। जिसमें बागबानी, लकड़ी का काम, मिट्टी के बर्तन, बिजली का काम आदि शामिल है। 2025 के अंत तक नई शिक्षा नीति के अंतर्गत कम से कम 50% छात्रों को वोकेशनल स्टडीज पढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा

जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि बच्चों को यदि उनकी मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाए तो वह बात को ज्यादा आसानी से समझ पाएंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए **नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022** के अंतर्गत पांचवी कक्षा तक बच्चों को उनकी मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाने का प्रावधान रखा गया है। अब शिक्षकों को पांचवी कक्षा तक बच्चों को उनकी मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा प्रदान करनी होगी। पाठ्य पुस्तकों को भी क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध कराना का प्रयास किया जाएगा और यदि पाठ्यपुस्तक क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध नहीं है तो इस स्थिति में बच्चों और शिक्षक के बीच बातचीत का माध्यम क्षेत्रीय भाषा होगा। कक्षा एक से बच्चों को दो से तीन भाषाएं सिखाई जाएंगी।

नई शिक्षा नीति : समग्र सोच

नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 के अंतर्गत छात्रों को अब कोई एक स्ट्रीम नहीं चुननी होगी। अब छात्र आर्ट स्ट्रीम के साथ साइंस स्ट्रीम भी पढ़ सकते हैं, साइंस स्ट्रीम के साथ आर्ट्स स्ट्रीम भी पढ़ सकते हैं। प्रत्येक विषय को अतिरिक्त पाठ्यक्रम ना मान के पाठ्यक्रम के रूप में देखा जाएगा जिसमें योग, खेल, नृत्य, मूर्तिकला, संगीत आदि शामिल है। एनसीईआरटी पाठ्यक्रमों को राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा के अनुसार तैयार करेगी। शारीरिक शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। वोकेशनल तथा एकेडमिक स्ट्रीम को अलग नहीं किया जाएगा जिससे कि छात्रों को दोनों क्षमताओं को विकसित करने का मौका मिले।